

# हिन्दुस्तान

प्रवेश समिति ने तैयार किया प्रस्ताव, 15 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे

## राज्य प्रवेश परीक्षा-2016 ऑनलाइन नहीं होगी

● लखनऊ। कार्यालय संवाददाता

प्रदेश के 630 इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई)-2016 के आवेदन 15 जनवरी से शुरू होंगे। आवेदन को समय पर पूरा करने के लिए इस बार प्रक्रिया को करीब एक महीने पहले शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। इसके लिए प्रवेश समिति की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव को विश्वविद्यालय के सेंट्रल एडमिशन बोर्ड (केब) की बैठक में रखा जाएगा। खास बात यह है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है।

**17-18 अप्रैल को परीक्षा**

एसईई-2015 के आवेदन 25 फरवरी के आसपास शुरू किए गए थे। बाद में आवेदन की समय सीमा विस्तारित किए जाने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में छात्र आवेदन भी नहीं कर सकते। इसके मद्देनजर 2016 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 15 जनवरी तक शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। उधर, जानकारों की मानें तो आवेदन प्रक्रिया मार्च के अन्तिम सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है। एसईई-2016 का आयोजन आगामी 17 और 18 अप्रैल को होगा। इसे बेहतर ढंग से कराने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

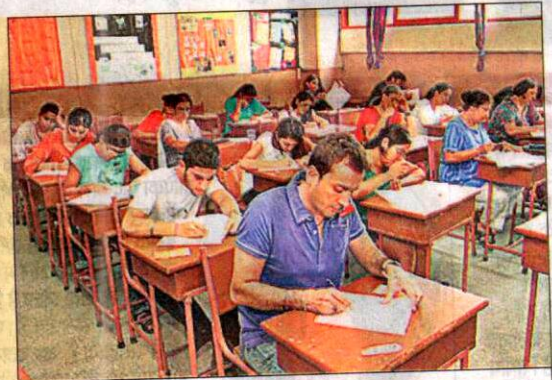
**एनआईसी को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी**

राज्य प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य तकनीकी काम अभी तक प्राइवेट एजेंसियों को सौंपे जाने

○ एसईई के जरिए यूपी के 630 इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में दाखिला

○ सेंट्रल एडमिशन बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

○ इस साल जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया



**ऑफलाइन परीक्षा ही होगी**

एसईई-2016 को ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। अब ये ऑफलाइन मोड पर ही होगी। जानकारी की मानें तो प्रदेश के सभी जिलों में तकनीकी उपलब्ध न होने के कारण ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले भी एक बार परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा करा चुका है। हालांकि, नतीजे बेहतर न मिल पाने के कारण दोबारा ऑफलाइन मोड पर आना पड़ा था।

**25% सीटों पर बाहरी छात्रों को मौका**

इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन एसईई में प्रदेश के बाहर के निवासी छात्रों को भी शामिल करने की कवायद में जुटा है। यहां की 25 प्रतिशत सीटों पर दूसरे राज्य के निवासी छात्रों को शामिल किए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भी भेजा गया है। ये कोटा प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले के लिए लागू किया जाएगा। इस पर शासन की मुहर की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस पहल को छात्रों की कमी की मार झेल रहे प्रदेश के कॉलेजों की स्थिति में सुधार के लिए अहम माना जा रहा है।

का रिवाज रहा है। इसको लेकर कई बार विवाद खड़े हुए। एसईई-2015 में तो लाख-लाख रुपए में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा बेचे जाने तक की

शिकायतें आई थीं। कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि इस बार ये सारी जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपे जाने की कवायद शुरू कर दी गई है।